[श्री रघुनाथ सिंह यादव]

ऐंड फास्ट रूल नहीं हो सकता है लेकिन साधारणतया 50 परसेंट से नीचे होना चाहिए । यह रूलिंग इन 1971, ए आई आर, पेज 1710 पर है :

"That in adjusting the claim of both the weaker and the stronger elements, the reservation for the former should be ordinarily less than 50 per cent although no flexible percentage could be fixed and the actual reservation must depend upon the relevant prevailing circumstances in each case."

इस तरह की रूलिंग के बाद अब कोई औचित्य नहीं है कि इस देश में इस विवाद को बढ़ाया जाये । इस सम्बन्ध में बिहार के मुख्य मंत्री, श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने जो किया है उसके लिए मैं उन्हें बधायी देता हूं । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक सर्वमान्य गाइडलाइन भेजी थी कि इस तरह से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए रिजर्वेशन किया जाये और उसी की तहत वहां पर रिजर्वेशन हुआ है । अब उसके लिए कोई आन्दोलन या उपद्रव करना राष्ट्र हित में नहीं है । जो सदियों से दबा और पिछड़ा वर्ग है, जो गरीबी और छूनाछूत से प्रभावित है, जोकि जातपांत के आधार पर पिछड़ गया है--उस वर्ग को उठाने के लिए विशेष अवसर देने ही होंगे । इस सम्बन्ध में डा० राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा था ऐसे वर्गों के लिए 60 फी सकडा नौकरियों तथा स्कूलों में आरक्षण देना चाहिए ।

काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में तीन मुख्य सिफारिशें की हैं । पहली सिफारिश यह है कि सभी व्यावसयिक कालेज, जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि एवं प्राद्योगिकी कालेजों तथा केन्द्रीय स्कूलों में हरिजन, गिरिजन, अल्पसंख्यक तथा अन्य वर्गों के छात्रों के लिए प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 70 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायें । दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों की सीधी भर्ती में स्थानों के आरक्षण के लिए विशेष उपबंध होगा जो वर्ग (1) में 25 प्रतिशत, वर्ग (2) में 33 प्रतिशत, वर्ग (3) में 33 प्रतिशत और वर्ग (4) में 40 प्रतिशत...

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण अगली बार, जब यह विषय आयेगा तब जारी रखियेगा ।

अब आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ होगी ।

17.30 hrs.

HALF AN-HOUR DISCUSSION

PERSONS LIVING BELOW POVERTY LINE

MR. CHAIRMAN: Now, we take up the Half-an-Hour Discussion. Dr. Laxminarayan Pandey.

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति जी, पिछली सरकार के समय में गरीबी हटाने के बारे में वायदे तो बहुत किये गये, आश्वासन भी बहुत दिये गये, लेकिन गरीबी घटी नहीं, बढ़ती चली गई । जहां गरीबी बढ़ी, वहां पर गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ी । अनेक योजनायें बनीं, लेकिन पिछली सरकार के समय में जो योजनायें बनीं, वे सब अव्यावहारिक योजनायें थीं, उन के कार्यान्वयन में भी दोष था और यही कारण था कि हम गरीबी हटाने की बात कहते रहे, परन्तु गरीबी हटी नहीं, बढती चली गई ।

सभापति महोदय, पिछले दिनों माननीय प्रधान मंत्री जी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह प्रदर्शित किया है कि हम ऐसे प्रयत्न करने जा रहे हैं जिन से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, उन का जीवन-स्तर ऊंचा उठेगा, यहां तक कि गांव में रहने वाले, विशेष कर निम्न स्तर पर रहने वाले जो लोग हैं—उन के जीवन में भी सुधार आयेगा । हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, उस के द्वारा गांवों में जा कर हम स्वच्छ, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था कर सकें, जहां पर रहने योग्य मकान नहीं हैं, वहां पर रहने योग्य मकान की व्यवस्था कर सकें, शहरों में कीचड़ भरे स्लम एरियाज हैं, उन को उठा कर वहां पर रहने वाले व्यक्तियों का जीवन उठा सकें—इन सब चीजों के लिये हम प्रयत्नशील हैं और मुझे संतोष है कि इस दिशा में हमारे किये गये प्रयत्न सार्थक सिद्ध हो रहे हैं । लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि इस सरकार द्वारा गरीबी हटाने की दिशा में कुछ नहीं किया जा रहा है मुझे खेद है कि विपक्ष के लोग जनभावना को नहीं देखते । माननीय सभापति महोदय, मैं स बारे में हिन्दुस्तान टाइम्ज में एक समाचार छपा था उसे उद्धृत करना चाहता हूं ।

"1966-76 decade marked dark are of Indian Economy".

इन वर्षों में कहा तो यह जाता हमारी इकानामिक-ग्रोथ काफी हो गई है, 6 प्रतिशत बढ़ गई है या इससे भी अधिक हो गई है लेकिन वास्तविकता यह थी कि हम 4 प्रतिशत भी ऊंची नहीं कर सके थे । लेकिन कहते रहे । यही बात इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में कही गई कि इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन बढ़ गई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण इन्दिरा डिकेट था ।

एक माननीय सदस्य : डायनेमिक डिकेड ।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मैं इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों से उद्धृत करना चाहता हूं, इस में कहा गया है—

"The Indira Gandhi decade 1966-76, was a dark era of Indian economy. There was continued deterioration in the economy putting back the clock of progress.

* * * *

"According to this study, the share of public sector saving in total net domestic saving, which was 30.2 per cent in 1964-65 and 23.1 per cent in the following year, ranged between 12 and 17 per cent....."

स से साफ सिद्ध होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति के सुधार में कोई प्रयत्न नहीं किये गये और उस का परिणाम हम को भुगतना पड़ रहा है । हमारी अर्थ स्थिति सर्वथा डांवाडोल हो गई । गरीब को आवश्यकतानुसार भोजन भी दुर्लभ हो गया, भूखे सोने वालों की संख्या करोड़ों हो गई ।

मैं एक दूसरे प्रश्न पर भी आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा—जिस में एक रिसर्च स्टडी हुई है—योजना आयोजन गरीबी के रेखा के लिये मानदण्ड तय किया था । मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

"While the Planning Commission has used the recommended nutritional requirements of 2,400 calories per person per day for rural areas and

[श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

2,100 calories correspondingly for urban areas to define "the poverty line," the study has used the yardstick of a per capita income per month of Rs. 75 for the same purpose."

यह केवल आयोग की उक्ति मात्र बन कर रह गई । और इस दिशा में काम कुछ भी नहीं हुआ ।

ऊपर के उदाहरण से सिद्ध होता है कि हम ने जितना तय किया था, क्या हम उस को उतना दे सके ? जितनी न्यूनतम आवश्यकता हो सकती है, उस न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर सके हैं और यही कारण है कि उस सारे प्लानिंग के पैटर्न को बदलने की क्रिया हम को करनी पड़ी ।

सभापति महोदय, एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि हमारा जो योजना का कार्यक्रम है या जो योजना की स्थिति है, हमने जो योजना बनायी है, उसके अनुसार हम गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वालों की संख्या को – जिसे कुछ लोग टोटल पापुलेशन का 49 परसेंट, कुछ लोग 45 परसेंट और कुछ लोग 50 परसेंट से ऊपर कहते हैं––1982-83 तक 33 परसेंट पर ला सकेंगे । यह हमारी योजना का लक्ष्य है । मुझे आशा है कि हमारा यह लक्ष्य पूरा होगा ।

इस गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वालों में शहरों में रहने वाले या गांव में रहने वाले लोगों की भी समान दयनीय स्थिति है । शहरों में रहने वाले लोगों की स्थिति भी खराब है, वहां के गांव के लोगों की स्थिति भी खराब है । वे लोग आवासहीन है, पेय शुद्ध जल नहीं है, दो जून भोजन नहीं है । आज देश में बहुत अधिक संख्या में––शहरों में भी और गांवों में भी–– आवासहीनों की है । यह संख्या पिछले सालों में बहुत बढ़ती गयी है क्योंकि पिछले सालों में ग्रामीण आवास योजना के बारे में या ग्रामोन्मुखी कार्यक्रम को ले कर सरकार ने कोई प्रयत्न ही नहीं किया था । गांवों में जो आवास की समस्या है, उस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया गया हम अगले पांच वर्षों में शहरों और गांवों में कितने आवास देख सकेंगे । यह ठीक है कि उस समय कुछ बड़े कारखाने देश में लगे लेकिन बड़े कारखानों की स्थापना से मनुष्य के पेट की इस ज्वाला को बुझाने में हम समर्थ नहीं हो सकते । उद्योग धंधों के क्षेत्र में भी हमारी यह कल्पना होनी चाहिए कि गांव गांव में हमारे उद्योग धंधे फैलें और हर हाथ को काम मिले इससे यह आशय नहीं कि बड़े उद्योग न खुलें किन्तु आवश्यकता अधिक छोटे उद्योगों की है । मुझे आशा है कि सरकार अब इस दिशा में प्रयत्नशील होगी । मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि सरकार के इस प्रकार के प्रयत्नों से गांवों की समस्या का भी समाधान हो सकेगा ।

हमारे विपक्ष के बंधु, विशेष कर कांग्रेस आई के बंधु यह कहते हैं कि हमारी सरकार ने कुछ अफ़ेक्ट ही नहीं किया, साल-डेढ़ साल में हमारी आर्थिक स्थिति में बड़ी खराबी आयी है । मेरा आप से निवेदन है कि इस साल-डेढ़ साल में हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है, हमारा इकोनोमिक ग्रोथ ठीक हुआ है, हमारा फारेन एक्सचेंज सरप्लस में है, जो पहले सरप्लस नहीं

था या आंकड़ों के आधार पर उसे सरपलस बनाया गया था लेकिन अब वास्तविक वृद्धि हुई है, हमारा आयात और निर्यात की स्थिति भी ठीक हुई है । यही कारण है कि आज हम संतुलित आर्थिक स्थिति की ओर जा रहे हैं जिस से लोगों का यह भरोसा होने लगा है कि हमारा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, देश आर्थिक प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है । आम उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में जो स्थिरता है, गिरावट भी है वह इसी का प्रमाण है ।

माननीय सभापति जी, ए अन्य दाण्डेकर वर्किंग ग्रुप ने जो फिगर्स दी हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों की संख्या 51 प्रतिशत 40 प्रतिशत या 42 प्रतिशत है, उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बजट की तीन प्रतिशत धनराशि 1977-78 में केवल एग्रीकल्चर सेक्टर पर या उस से सम्बन्धित क्षेत्र पर खर्च होगा । इस राशि में और भी बढ़ोतरी हो सकती है । यदि हम कृषि की उन्नति कर पाते हैं, उस में काफी आगे बढ़ पाते हैं तो हम ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को हल करने की दिशा में काफी आगे बढ़ सकते हैं । प्रकारान्तर में इससे शहरों की बेकारी पर भी असर पड़ेगा । हमारे ग्रामीण उद्योगों की योजना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ।

आज यह कहा जा रहा है कि बेरोजगारों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है । इन बेरोजगारों में शिक्षित, प्रशिक्षित, अर्द्धशिक्षित, अशिक्षित सभी हैं । इनकी संख्या में जो निरन्तर वृद्धि हो रही है, उस के बारे में भी हमारा प्रयत्न है कि उसे हम रोकें और मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारे आगे के प्रयत्नों से वह रुकेगी । माननीय प्रधान मंत्री जी ने दस वर्षीय अवधि हेतु घोषित की है । हमारी योजनायें भी इसी प्रकार की हैं ।

मैं इस सदर्भ में यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि क्या हम ने जो इस प्रकार की योजना बनाया है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों की संख्या में निश्चित ही और गिरावट आयेगी और हमारे यहां लोगों का जीवन स्तर और ऊंचा उठेगा उस दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है ? अगले पांच वर्षों में हम प्रति व्यक्ति औसत आय में कितनी वृद्धि कर पायेंगे अगले पांच वर्षों में हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना होगा ? हमारे रूरल डेवलपमेंट में कितना राशि लगेगी कृषि उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा ? हमारा इकानामिक ग्रोथ कितना होगा ?

मान्यवर, हमारे सामने जो भीषण ज्वलंत समस्या है कि नौजवान शिक्षा प्राप्त कर के, बिना शिक्षा प्राप्त कर के भी सड़कों पर बेकार घूम रहे हैं । यह हमारे लिए चेतावनी है कि हम अपने नौजवानों के लिए काम के अवसर उपलब्ध नहीं कर सके । मैं पूछना चाहता हूं कि उन को काम दिलाने के लिए अब तक हमने कौन सी योजनाएं हाथ में ली हैं । हमने कौन सी योजना तैयार की है । पिछली सरकार ने इस दिशा में जो गलतियां कीं, दोषपूर्ण और अव्यावहारिक योजना प्रस्तुत कर इस दिशा में कमियां बनाये रखीं, हमारी आर्थिक स्थिति में गड़बड़ी चलती रही, उन को ठीक कर

[श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

के हम देश के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें और उनकी स्थिति में सुधार ला सकें : इस हेतु हमारे उठाए गये कदम प्रस्तावित योजनाए व उनकी पूर्ति की ? सम्पावधि क्या है ? हमारी राष्ट्रीय वेतन नीति क्या होगी ? हमारी विभिन्न वस्तुओं औद्योगिक उत्पादनों व कृषि उपजों केलिये दाम निती क्या होगी वय हम खर्च की सीमा बाधने जा रहे हैं।

अन्त में मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं । क्या सरकार इस बारे में सावधान हैं कि स्थान स्थान पर इंडस्ट्रीज में जा कर कुछ लोग योजनापूर्वक यह प्रयत्न कर रहे हैं कि उत्पादन ठीक न हो इंडस्ट्रीज ठप्प हों वे चलें नहीं ? अगर हैं तो इन प्रयत्नों को विफल करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं जिनसे हमारे उत्पादन पर विपरीत असर इस प्रकार से न पड़े मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार क्या कर रही हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं समझा नहीं क्या पूछना चाहते हैं ?

सभापति महोदय यह पूछना चाहते हैं कि 1982–83 तक आप क्या करने वाले हैं चेंज लाने के लिए ?

श्री मोरारजी देसाई : ज्यादा लोगों को रोजी देने के कार्यक्रमों से ही गरीबी दूर होगी । कोई दूसरा इसका तरीका नहीं है । इसीलिए हम उसी के ऊपर सब से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं । ग्रामीण विकास की योजना को इसीलिए हमने प्रायोरिटी दी हैं । इसका कारण यह भी है कि वहीं ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे, नीचे के स्तर पर रहते हैं । वहां काम देने के लिए गृह उद्योगों को हम ज्यादा बढावा दे रहे हैं । घर घर में ये हो जाएं तो उनका जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा । खेती को बढाने के लिए हम उसके ऊपर पहले से काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं । हमारी योजना में चालीस प्रतिशत तक उसके ऊपर खर्च करने की व्यवस्था है । केवल व्यवस्था कर दी हो और खर्च हो नहीं ऐसी बात नहीं है । खर्च बराबर होगा और ठीक ढंग से होगा ताकि यह काम आगे बढ़े ।

पहले ग्राम्य विस्तार के लिए जो योजनायें बनती थी वे इस आधार पर बनती थी कि केन्द्र की योजनाओं पर ज्यादा खर्च होता था । जो बड़े बड़े उद्योग होते थे पब्लिक सैक्टर वगैरह में होते थे उन पर ज्यादा खर्च होता था । उसको भी हम बढ़ाते रहते हैं लेकिन हम उनको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं । प्राथमिकता ग्राम्य विस्तार के कामों को ही दे रहे हैं । इसीलिए प्रदेशों की जो योजनायें हैं उन पर कुल खर्च केन्द्र की योजना से ज्यादा होगा । यह पहली बार किया गया है और यह इसी उद्देश्य को सामने रख कर किया गया हैं कि ग्राम्य विस्तार में ज्यादा रोजगार मिले ।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । राजस्थान को आप लें । हर एक जगह अलग अलग हो रहा हैं । लेकिन राजस्थान में हर एक गांव में हर एक देहात में पांच सब से नीचे के सब से गरीब

कुटुम्बों को लिया गया है । करीब डेढ़ लाख ऐसे कुटुम्बों को लिया गया हैं जिन को ऊपर उठाना है । पूरे कंसैंट्रेशन से वहां यह काम हो रहा है । इस में से एक लाख के करीब फैमिलीज तक तो पहुंचा जा चुका है और बाकी तक पहुंच जाएंगे । फिर दूसरे परिवारों को लेंगे । फिर इससे आगे बढ़ेंगे । इस तरीके से सभी जगह काम हो रहे हैं ।

पशुपालन की योजना को भी इसीलिए हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि एक दो गाय रख कर इंसान अपना गुजारा अच्छे ढंग से कर सके । पशुपालन के ऊपर भी हम ज्यादा ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं ताकि ऐसे उद्योग धंधे उनको मिल जाए जिन को घर में बैठ कर वे लोग चला सकें और देहातों से लोग भाग कर शहरों की तरफ न आएं और शहरों में गन्दी बस्तियों का निर्माण न हो । इससे गुनाहगीरी भी बढ़ती है । उसको रोकने का भी यही तरीका है और इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं ।

शहरों में भी ज्यादा लोगों को रोजी मिले उस ओर भी हम ध्यान दे रहे हैं । ऐसी बात भी नहीं है कि बड़े उद्योगों को छोड़ कर उनकी उपेक्षा करके हम चल रहे हों । उन पर भी ध्यान दे रहे हैं । दोनों पर ध्यान दे रहे हैं । परन्तु प्राथमिकता उसके ऊपर होगी जहां ज्यादा लोगों को काम मिले और इसीलिए मिनिमम नीड्ज प्रोग्राम पर हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं । उत्पादन में वृद्धि हो इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं । आपने देखा ही होगा कि पिछले आठ दस साल में इस साल पहली बार दीवाली के मौके पर या दूसरे त्यौहारों, ईद वगैरह के मौके पर लोगों को जितनी चीजें चाहियें थी वे सारी चीजें मिली हैं और पूरी मात्रा में मिली हैं और पहले से कम दामों में मिली हैं । और उसके साथ उनको क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ा । यह बताता है कि कितनी प्रगति हो रही है । और इससे हमें पूरा संतोष नहीं है । जब तक हर एक को न मिले तब तक हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं । यही मैं कह सकता हूं ।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Mr. Chairman, Sir,....

MR. CHAIRMAN: Mr. Lakkappa, I will request you to just put the question.

SHRI K. LAKKAPPA: This is a very vital issue which is being discussed here. I would therefore request you to kindly see that Half-an-Hour discussion is not limited to half-an-hour. It could have been taken earlier instead of at 5.30 P.M. My friend, has raised a very vital issue regarding the unemployment, poverty and inequality of income. These are relative phenomena. Government is not working out any strategy to tackle this problem. The success of any Government would depend upon good planning. The hon. Prime Minister, for the last 1 1/2 years, has been saying that the Government's object is to banish poverty, unemployment and inequality in incomes. Today we are facing financial crisis and the economy of this country is in a shambles and the basic issues have not been solved. Why has the Government not been very earnest about this? What is the difficulty? Whether there is any co-ordination? Is there any political will to solve these problems? The concept of poverty is somewhat wider and not includes not merely those who are mployed and poor but also those who are fully or partly employed. In every State this concept is prevalent. Then there was a feeling that the Planning Commision's report was not encouraging. Even the concept of the public sector being diluted by the present Government will add on to the private sector. Therefore, we have got an apprehension whether the Government would work out a strategy so that this explosive situation is averted. Only three years are left in so far as

[Shri K. Lakkappa]

the present Government is concerned. The hon. Prime Minister, when he came to power, declared that within five years, stage by stage, poverty would be removed. But for the last 1 1/2 years, nothing has been done either by the Industries Minister or by any other Minister co-ordinating with the Prime Minister. Therefore I would like to know what exactly the strategy that would be adopted by the Government to tackle these basic economic issues. Whether the hon. Prime Minister will give due consideration before diluting the public sector which would add on to the private sector? If this is done, there will be further concentration of wealth in the hands of a few. In regard to the dilution of the public sector, there is a difference of opinion in your own party. I would like to know whether the hon. Prime Minister will give thought over this matter and see that the progressive socialist programmes are given necessary encouragement.

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : गरीबी की रेखा के नीचे जितने आदमी हैं, उनके सम्बन्ध में विवाद हो सकता है, लेकिन इतनी बात तो सही है कि गरीबी के साथ-साथ एक और बीमारी है जो गरीबी को और गहरा बना देती है, और वह है विषमता । 50 प्रतिशत घरों में समूचे देश का वेतन, जो आय है वह 82 प्रतिशत जाता है और 50 प्रतिशत में केवल 17 प्रतिशत आता है । उसी प्रकार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी आय की विषमता है । यहां नहीं जो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है और दूसरी जगह की है, उसके अनुसार 33 प्रतिशत जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनकी सारी सम्पत्ति, समूचा उनका जो एसेट्स हैं वह 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, 11 प्रतिशत का 500 से ज्यादा नहीं है । मेरे कहने का मतलब यह है कि, ठीक है, जनता सरकार ने 10 वर्षों में गरीबी दूर करने के लिये जो ग्रामोन्मुखी अर्थ नीति बनाई है, वह सचमुच में अभिनन्दनीय है, परन्तु मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि यदि हम विषमता को भी दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे तो जिस प्रकार से हरित क्रांति भी अमीरों के हक में गई और गांव के गरीब ज्यादा गरीब हो गये, तो अगर हमने ग्रामोन्मुख नीति के साथ-साथ भूमि सुधार के काम नहीं किये और जमीन के सम्बन्ध में पुनर्वितरण की व्यवस्था नहीं की और जो रोजगार देने वाले हैं, वह गरीबों को नहीं दिये, तो क्या इस तरह से इकनामिक इमबैलेन्स नहीं होगा ?

SHRI CHITTA BASU (Barasat): This half-an-hour discussion is based on the answer given to an earlier question in this House on the 22nd November, 1978. On the basis of that answer, it appears that even after the successful implementation of the Sixth Plan, 38 per cent of the people would still remain under the poverty line in 1982-83. Some economists have also indicated that even in 1987-88, there will be 27 per cent people below the poverty line if we achieve what is envisaged in the 6th Plan. In this context, may I know from the hon. Prime Minister, what is the perspective plan for the country showing by which year, by which Plan, the country will be free from bane of poverty?

Experience has borne it out that during the preceding Plans, the inequality as increased. I have got figures to show that both in the urban and rural areas. What is the particular strategy for reducing this yawning gap of inequality? He has mentioned in his reply that the land reforms are one of the major strategy of eliminating or reducing poverty in the rural areas. Is it not a fact that the implementation of land reforms is tardy and there has been growing incidence of landlessness? Will the Government take appropriate measures for the speedy and prompt implementa-

tion of land refoms, which has been tardy and fallen much short of the target?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): My hon. friend Shri Lakkappa, as usual, condemns this Government. This is what he said: "Nothing is being done. Things have been happening; they are not coordinated. There is no policy." What greater condemnation than that, can there be? I do not know whether I can satisfy him. But I would like to tell him that we are not interested in diluting the public sector. We are not diluting it at all. Show where public sector has been disputed. Let it be pointed out. Then I will prove to them that we are attending to it more than they were doing, because we are trying to see that the public sector works far more satisfactorily than it has done. Not that we are rejecting it but we are not making a gospel of public sector. We believe in a mixed economy. It has been so throughout the last 30 years. It is not I, who am saying that we believe in a mixed economy. When his leader was there, then also the same thing was said, *viz.* that it was a mixed economy. They did not say anything else.

There is no question of liquidating the other thing. Therefore, why are they wanting to foist it on me? I don't consider it a mistaken path. He will always be mistaken, for others; not for himself. I am glad he is accepting now that he is mistaken. But he is still sitting there. How is he mistaken then?

AN HON. MEMBER: Are you referring to Mr. Lakkappa or Mr. Chandrappan?

SHRI MORARJI DESAI: I am only referring to the hon. Member who spoke. I should not speak to his companion.

Mr. Lakkappa then said that we say that we are going to remove unemployment in 10 years. That is what we have said. That we said last year. That is, 10 years from last year. He says I will be here now only for 3 years. I do not know whether I will be here for 3 years, or for 10 years. Nobody can say that.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): Your Minister of Industry Mr. George Fernandes said that he will remove unemployment in 5 years. He has made a public statement.

SHRI MORARJI DESAI: No; I have not heard him say that.

SHRI K. LAKKAPPA: In Bhopal he has made a statement.

SHRI MORARJI DESAI: I have not read it; and I don't think he will make such a statement.

MR. CHAIRMAN: There is a report in the papers.

SHRI MORARJI DESAI: Papers report many things. How could he say that? If he has made that statement, I will correct it.

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF (Bangalore North): Your Industry Minister has also said that it is a non-performing Government. How do you expect it to solve the unemployment problem?

SHRI MORARJI DESAI: He may have said that, to please you perhaps; I do not know.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: He wants to threaten you.

SHRI MORARJI DESAI: Nobody can threaten me; and I don't threaten anybody. So, there is no question of it. Therefore, how long I will be here is not material. This is how we are working towards it. I am quite sure that those who come afterwards also will take up the same line, or even improve on it, but not worsen it. That is my expectation. One does not work for 3 or 4 years; but one works for a perspective plan. That is what was asked: what was the per-

[Shri Morarji Desai]

spective. The perspective is that we want, within 10 years, to see that there was no unemployment left. That does not mean that we have done everything that we wanted to do. Then it is a question of making it much better than what it is. But this can be done only by giving them full employment.

And that is what we are doing and that is what I had said before to the mover, who had first said these things. Therefore, I need not repeat it.

Then my hon. friend Dr. Ramji Singh said something. I do not quite understand what he wanted me to say.

18 hrs..

AN HON. MEMBER: Sarvodaya.

SHRI MORARJI DESAI: Well, sarvodaya, that is what we all believe in. But by merely saying sarvodaya, it is not going to be achieved; and that is exactly the reason why we are attending to the poorest people first; and that is why we are not going to widen the distance between the two. As a matter of fact, that is our main attempt.

We are also seeing that the same houses which have more and more industries do not get more and more licences. But we cannot pull them out. That will create unemployment and that is not right. But we are trying to see that that is also done in public interest and not for private interest. That is what we are trying to do.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Excuse me, Sir, your Minister of Industry, in reply to my letter, has written to me that four licences for cement factory have been given to the big business in my own constituency. When I wrote about it, he said, we have not yet decided not to.....

(Interruptions)

SHRI MORARJI DESAI: That we cannot say, that if nobody is coming forward we will not ask them to take it up. After all, it has to be produced.

(Interruptions)

Public sector cannot take every thing. That is how the mess was made by attempting too much which you cannot do. We have got to see that we become effective in whatever we do.

SHRI K. LAKKAPPA: That is what we say that you are diluting.

SHRI MORARJI DESAI: I am not diluting. I am not going in a mad way as they were doing. That is all. We are bringing sanity into this public sector and not trying to dilute it.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore): It is commanding height.

SHRI MORARJI DESAI: They have only commanded heights in words. We do not apply any high flown adjective. We want to do the deeds so that people are satisfied. That is what we want to do. Otherwise, one can say anything. I do not believe in slogans. We do not believe in slogans, because slogans take away our attention from the main thing and only slogan-mongering goes on, as it has gone on sometimes. It has become a fashion. But we do not want to do that.

(Interruptions)

How is it a slogan? It is being done. But you cannot do it mathematically; first year this and second year this. The whole thing has to be built up. That is being done. Then you will find far quicker progress; in the later years, you will find that. I gave you an example of what is being done. It is also done in Punjab; it is done in Gujarat; it is done in other places, and that is happening; and therefore one can go saying that.

Therefore, my hon. friends should not be so anxious about our health in any case, about the health of my Party or my Government.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Some people.

SHRI MORARJI DESAI: Some people may be concerned. But that is a common malady. It is not a question of this party or that party; it is available everywhere.

(Interruptions)

So, you need not tell me this. That will be improving. You will see that is improving. It is going on improving, and that is how we go on doing. I gave an indication of what was happening. you are seeing what is happening. Inflation has been held.

AN HON. MEMBER: Checked.

SHRI MORARJI DESAI: Held. How could it otherwise be held? It has not been held in other countries except in India and that has been done in these 18-19 months. And still we have to be very careful lest it should again go off. That is why we are trying to do that.

My hon. friend has said that we are absolutely in a mess in economic matters. I do not know how it is there that the economy is in a shambles. It is only in his language, not in actual facts. That is why I will plead with him not to exaggerates. Even in his exaggeration, there should be no exaggeration. That is all I would say. I take a certain minimum from him. All right. But it goes much beyond that. Then it ceases to have any interest for me. That is why I am pleading with him not to make me lose my interest in what they are saying.

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Your financial institutions are not helping the poor.

SHRI MORARJI DESAI: I have talked to them personally; guidelines have been given. We are watching it also and they are going about it but we do not go about it in the manner in which it had been done in the past when loans were given by banks indiscriminately on the recommendations of some people in power and therefore instalments are not being returned. Banks become bankrupt that way. We want to see that every rupee that is given comes back and also helps the person to whom it is given; we are trying to see that people are given help. You must have read, I think; one of the banks which I had gone to open in Poona, they decthat every month every branch will lared that is the Maharashtra Bank, that every month every branch will bring up two men in that area to see that they become self-employed, satisfactorily employed and give them loan for that purpose. They have 500 branches. Therefore, it will be one thousand persons per month. I have asked the other banks to do this. We are trying to push this up. We are trying to do this in this manner so that the banks also perform that task. The task of the banks is not merely to help big business; they have also to be helped but preference must be given to the people who are more in need, to enable them to come up and that is being done. Past habits do not die quickly. It is a matter of satisfaction that they are doing it.

I can quite understand the impatience; we should have some impatience, but not such impatience that we retard the work and not encourage the people who are doing it. That is how we are looking at it... *(Interruptions)*

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: Technical people should be given help for self-employment schemes.

SHRI MORARJI DESAI: We are helping the technical people for self-employment. That is a better way of doing it rather than make everybody a wage earner. Let them be self-employed more and more. That is why in villages, they take to cattle breeding, poultry farming and so on; there is more intensive agriculture. We want to see that people who are

[Shri Morarji Desai]

holding only 1-5 acres of land are enabled to live more satisfactorily even in that area, in the small area that they have by intensive farming and we try to help them not only with money but with advice, suggestions. That is why we give importance to cottage industries. Every person had this knowledge at one time and the village was humming with cottage industries and the country was prosperous; that is what we should bring back. It requires the removal of inertia from the people which has got hold of all of us on account of past tradition. That is where I want the help of all of you to see that this climate is created. Wherever anybody wants to take it up, if he is not helped, please bring it to my notice and I will see that he is helped. That is what we are trying to do.

Therefore, I would assure my hon. friends that this government is alive to it and we are also alive to the fact that we cannot perform magic. We must be realistic, but not realistic in such a way that results are tricking or very negligible. That is all that I have to say.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 a. m. on Tuesday the 12th December 1978.

18.10 hrs. ..

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 12, 1978/Agrahayana 21, 1900 (Saka)